



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)  
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 586]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 29, 1983/पोष 8, 1905

No. 586]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 29, 1983/PAUSA 8, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1983

आदेश

का०आ० 937(अ)/18कक/आई०डी०आर०ए०/83 :—  
केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास  
मंत्रालय के आदेश सं० का०आ० 134(अ)/18कक/आई०  
डी०आर०ए०/79 तारीख 13 मार्च, 1979 द्वारा यथा  
उपांतरित आदेश सं० का०आ० 529(अ)/18कक/आई०डी०  
आर०ए०/74 तारीख 6 सितम्बर, 1974 द्वारा (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) सचिव, बन्द रुग्ण  
उद्योग विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार को (जिसे अब सचिव,  
औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार कहा  
गया है) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिकृत व्यक्ति  
कहा गया है) मैसर्स इंडिया बैल्टिंग एण्ड काटन मिल्स  
लिमिटेड, सीरमपुर, पश्चिमी बंगाल का (जिसे इसमें इसके  
पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) तारीख 6  
सितम्बर, 1974 से पांच वर्ष की अवधि के लिये प्रबन्ध  
ग्रहण करने के लिये प्राधिकृत किया था,

और केन्द्रीय सरकार की यह राय थी कि लोकहित में  
यह समीचीन है कि उक्त अधिसूचित आदेश को उपयुक्त  
पांच वर्ष के समाप्त होने के बाद प्रभावी बना रहना  
चाहिये और उसमें 31 दिसम्बर, 1983 तक की जिसके  
अन्तर्गत वह तारीख भी है, अतिरिक्त अवधि के लिये इसे  
जारी रखने के लिये समय-समय पर निर्देश जारी किये थे,  
(देखिए भारत सरकार के औद्योगिक विकास विभाग सं०  
का०आ० 512(अ)/18कक/आई०डी०आर०ए०/79, तारीख  
4 सितम्बर, 1979, सं० का०आ० 749(अ)/18कक/  
आई०डी०आर०ए०/80, तारीख 5 सितम्बर, 1980, और  
सं० का०आ० 684(अ)/18कक/आई०डी०आर०ए०/81,  
तारीख 4 सितम्बर, 1981, सं० का०आ० 125(अ)/  
18कक/आई०डी०आर०ए०/82, तारीख 5 मार्च, 1982,  
सं० का०आ० 648(अ)/18कक/आई०डी०आर०ए०/82,  
तारीख 4 सितम्बर, 1982, सं० का०आ० 158(अ)/  
18कक/आई०डी०आर०ए०/83, तारीख 4 मार्च, 1983  
तथा सं० का०आ० 386(अ)/18कक/आई०डी०आर०ए०/  
83, तारीख 31 मई, 1983,

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में यह  
समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उक्त

प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा, 30 जून, 1984 तक की और अवधि के लिये जारी रखा जाये,

अतः केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 30 जून, 1984 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है की और अवधि के लिये प्रभावी रहेगा ।

[फा०सं० 2(14)/80-सी०यू०एस०]

ए०पी० सरवन, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 29th December, 1983

### ORDER

S.O. 937(E)|18AA|IDRA|83.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 529 (E)|18AA|IDRA|74, dated the 6th September, 1974 as modified by the Order No. S.O. 134(E)|18AA|IDRA|79, dated the 13th March, 1979 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government had authorised the Secretary, Closed and Sick Industries Department, Government of West Bengal, now called Secretary, Industrial Reconstruction Department, Government of West Bengal (hereinafter referred to as the said authorised person) to take over the management of Messrs. India Belting and Cotton Mills Limited, Serampore, West Bengal (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) for a period of

five years from the 6th September, 1974;

And, whereas, the Central Government being of opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect after the expiry of the period of five years aforesaid, had issued directions from time to time, for such continuance for a further period upto and inclusive of the 31st December, 1983 (vide orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Nos. S.O. 512(E)|18AA|IDRA|79, dated the 4th September, 1979 S.O. 749(E)|18AA|IDRA|80, dated the 5th September, 1980, S.O. 684(E)|18AA|IDRA|81, dated the 4th September, 1981, S.O. 125(E)|18AA|IDRA|82, dated the 5th March, 1982, S.O. 648(E)|18AA|IDRA|82, dated the 4th September, 1982, S.O. 158(E)|18AA|IDRA|83, dated the 4th March, 1983, and S.O. 386(E)|18AA|IDRA|83, dated the 31st May, 1983;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said industrial undertaking by the said authorised person should continue for further period upto 30th June, 1984;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industrial (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of 30th June, 1984.

[File No. 2(14)|80-CUS]  
A. P. SARWAN, Jt. Secy.